भारत के अगले सीजेआई होंगे, जस्टिस सूर्यकांत

सीजेआई गवई ने जस्टिस सूर्यकांत से मुलाकात कर अपना रिकमंडेशन लैटर सौंपा

- जस्टिस गवई जो 24 नवम्बर को रिटायर हो रहे हैं, से केन्द्र सरकार ने अपने उत्तराधिकारी के नाम की अनुशंसा करने को कहा था।
- मूलतः हरियाणा के जस्टिस सूर्यकांत कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं, जैसे धारा 370 हटाना, इलैक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक ठहराना, स्पायवेयर पैगसस केस और राजद्रोह कानून को रद्द करना आदि।

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जो 24 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश की।

सरकार ने पिछले सप्ताह मुख्य न्यायाधीश गवई को एक पत्र लिखकर उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसी नाम की सिफारिश करने को कहा था। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश गवई इस समय भूटान दौरे पर थे। गवई ने अपने वापसी के तुरंत बाद सोमवार (27 अक्टूबर, 2025 को सिफारिश) को सिफारिश पत्र के साथ न्यायमूर्ति सूर्यकांत से मुलाकात की, यह दिन दिवाली की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट का पहला कार्य दिवस था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलो का हिस्सा रहे है, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 370 का निरस्त करना, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, शामिल है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत उस बैंच का भी हिस्सा थे, जिसने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक ठहराया था। वह पेगासस स्पाइवेयर मामले और देशद्रोह कानून के निलंबन वाली बैंच का भी हिस्सा थे।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। अपने गृह नगर से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपनी कानूनी प्रैक्टिस की शुरुआत हिसार जिला अदालत से की और 1985 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत शुरु करने के लिए चंडीगढ़ चले गए।

वह 7 जुलाई, 2000 को हरियाणा के सबसे कम उम्र के महाधिवक्ता बने और मार्च 2001 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए गए। 9 जनवरी, 2004 को उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। अक्टूबर 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

उन्हें 24 मई, 2019 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 9 फरवरी, 2027 तक रहेगा।

सितम्बर में 1.51 करोड़ उपभोक्ताओं ने किया मोबाइल नंबर बदलने का आवेदन

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए सितंबर महीने में 1.51 करोड़ उपभोक्ताओं ने आवेदन किया।

संचार मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि कुल 1.51 करोड़ उपभोक्ताओं में से जोन-1 (उत्तर एवं पश्चिम भारत) के 84.5 लाख और जोन-2 (दक्षिण एवं पूर्वी भारत) के 66.8 लाख उपभोक्ता शामिल हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश सर्किल से सबसे अधिक 20.8 लाख उपभोक्ताओं ने एमएनपी के लिए आवेदन किया। दूसरे स्थान पर 14.5 लाख के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर्किल का स्थान रहा। सितंबर में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या अगस्त की तुलना में 0.61 प्रतिशत बढ़ कर 99.56 लाख पर पहुंच गयी। इसमें 93.89 लाख मोबाइल ब्रॉडबैंड सबस्क्राइबर थे। सबसे अधिक 50.55 लाख ब्रॉडबैंड सबस्क्राइबर रिलायंस जियो के थे। भारती एयरटेल 31.04 लाख के साथ दूसरे और वोडाफोन आइडिया 12.78 लाख के साथ तीसरे स्थान पर रहा। मंत्रालय के अनुसार, सितंबर में रिलायंस जियो के मोबाइल सबस्क्राइबर 0.68 प्रतिशत, बीएसएनएल के 0.57 प्रतिशत और भारती एयरटेल के 0.11 प्रतिशत बढ़े। वोडाफोन आइडिया के सबस्क्राइबरों की संख्या 0.37 प्रतिशत घट गयी।

दूसरे चरण की एसआईआर कवायद आज से शुरु

12 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की नई मतदाता सूचियां बनेंगी

- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज प्रैस कॉन्फ्रैंस में एसआईआर प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी और कहा अगर किसी मतदाता को दो जगह नाम होने पर दो फॉर्म मिल जाते हैं तो बेहतर होगा वह एक ही फॉर्म जमा करवाएं, वरना उसके कृत्य का अपराध माना जाएगा।
- दूसरे चरण में राजस्थान में भी एसआईआर प्रक्रिया शुरु होगी। इसके अलावा मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, प.बंगाल, तमिलनाडु, गोवा के साथ 4 केन्द्र शासित प्रदेशों में भी एसआईआर प्रक्रिया शुरु होगी।

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विषेश गहन पनरीक्षण अर्थात स्पेशल इन्टेंसिव रिविज़न (एसआईआर) का काम मंगलवार से शुरू करने की घोषणा की है जो सात फरवरी तक संपन्न कर लिया जायेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को यहां एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में एसआईआर के दूसरे चरण के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए विश्वास जताया कि इस संवैधानिक कार्य में आयोग को सभी राज्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में दूसरे चरण में एसआईआर कराया जाना है, उनमें अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़ , गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों की मतदाता सूचियों में आज आधी रात के बाद तब तक कोई बदलाव नहीं किया जायेगा जब तक कि एसआईआर का काम संपन्न नहीं हो जाता। इसके साथ ही इस कार्य से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले आयोग की अनुमति से ही किये जा सकेंगे।

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार एसआईआर के दूसरे चरण में तीन नवंबर तक फार्मों की छपाई और कर्मचारियों का प्रशिक्षण होगा, चार नवंबर से चार दिसंबर तक बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ), प्रशासन के वॉलंटियर और राजनीतिक दलों के एजेंटों के माध्यम से घर-घर जाकर छपे हुए निर्वाचक गणना फार्मों का वितरण और उन्हें वापस एकत्रकर मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के पास जमा करवाने की प्रक्रिया चलेगी।

कार्यक्रम के अनुसार गणना फार्मों की प्राप्ति के आधार पर संबंधित राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों की नयी मतदाता सूची का मसौदा नौ दिसंबर को प्रकाशित कर दिया जायेगा और उसी दिन से आठ जनवरी 2026 तक उन पर दावे और आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। नौ से 31 जनवरी तक नोटिस और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी और पक्की मतदाता सूची सात फरवरी को जारी कर दी जायेगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एसआईआर के पहले चरण में पूरे उत्साह से भाग लेने के लिए बिहार के साढ़े सात करोड़ मतदाताओं की पूर्ण भागीदारी को लेकर उनके प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि बिहार की पक्की सूची पर दावे और आपत्तियां शून्य के बराबर हैं, जो दर्शाती हैं कि राज्य की मतदाता सूची अधिकतम रूप से शुद्ध है। उन्होंने इन राज्यों के मतदाताओं को कानून के अनुसार केवल एक ही मतदाता गणना फॉर्म जमा कराने की सलाह दी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार की ही तरह एसआईआर के दूसरे चरण में भी 2002 से लेकर 2004 के बीच में करायी गयी पिछली एसआईआर के बाद तैयार सूचियों को मिलान का आधार बनाया जायेगा। इन राज्यों और क्षेत्रों की वर्तमान सूचियों के मिलान का कार्य इनके मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) ने कर लिया है।

बिहार में एसआईआर के राजनीतिक विरोध के बारे में एक सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वह ऐसा नहीं मानते कि वहां राजनीतिक दलों का विरोध था। राज्य में 12 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के 1.06 लाख बूथ स्तरीय एजेंटों ने बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ बढ़ -चढ़ कर सहयोग किया। सभी जिला अध्यक्षों ने भी इस कार्य में पूरा सहयोग दिया और चुनाव से पहले आयोग के दौरे में इन दलों ने नेताओं ने एसआईआर की सराहना की।

'अगर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनाव प्रचार के लिए उतारा है, इस उम्मीद में कि उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन मोदी की सत्ता के चरम पर भाजपा अपने किसी खास को मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है।

लेकिन पार्टी उम्मीद में जी रही है!!!

रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का सफल टैस्ट किया

मॉस्को, 27 अक्टूबर। रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड, यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवस्तनिक-9एम739 का सफल परीक्षण किया है। रूस ने दावा किया है कि यह मिसाइल अनलिमिटेड रेंज वाली है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इसके सभी टेस्ट पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पहले कई एक्सपर्ट यकीन नहीं करते थे कि ऐसा हथियार भी बन सकता है, लेकिन यह हकीकत बन चुका है।

- पुतिन ने कहा, इसकी अनलिमिटेड रेंज है, इसे कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता।

रूसी सेना के प्रमुख वैलेरी गेरेसिमोव ने बताया कि मिसाइल का सफल टेस्ट 21 अक्टूबर को किया गया। इस टेस्ट में बुरेवस्तनिक ने करीब 15 घंटे तक उड़ान भरी। इस दौरान मिसाइल ने 14 हजार किलोमीटर की दूरी तय की। गेरेसिमोव ने यह भी बताया कि यह मिसाइल की अधिकतम रेंज नहीं है, यह इससे अधिक दूरी भी तय कर सकती है।

रूस ने ब्यूरेवस्तनिक को एक नाभिकीय-प्रेरित क्रूज मिसाइल के रूप में पेश किया है यानी इसमें एक छोटा परमाणु रिएक्टर भी रहेगा जो मिसाइल को अनवरत ऊर्जा देगा। जिससे उसकी रेंज सैद्धान्तिक तौर पर लगभग अनंत हो सकती है। अगर यह पूरी तरह से सच हुआ तो वाकई रूस दुनिया का पहला देश होगा, जिसके पास इतनी ताकतवर नाभिकीय-प्रेरित मिसाइल होगी।

आसियान सम्मेलन में रूबियो के अलावा कई नेताओं से भी मिले जयशंकर

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर। भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कुआलालंपुर गए विदेश मंत्री डा.एस जयशंकर ने सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो और कई अन्य देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। डा. जयशंकर ने इन नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात की।

- इनमें न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, वियतनाम आदि देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल थे

रूबियो से मिलने के बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनके बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात हुई। उन्होंने कहा , "आज सुबह कुआलालंपुर में मार्क रूबियो से मिलकर खुशी हुई। हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा की।"

विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ ाने और एक स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को विकसित करने के बारे में बात की। उन्होंने मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हाजी हसन से भी मुलाकात की। द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति पर चर्चा के साथ-साथ म्यांमार की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

डा. जयशंकर आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ से भी मिले। उन्होंने जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से मिलकर

द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा की। दोनों के बीच सहयोग के अगले दशक के लिए संयुक्त दृष्टिकोण को लागू करने के बारे में मिलकर काम करने पर सहमति हुई। उन्होंने वैश्विक स्थिति और हिंद-प्रशांत सहयोग पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

डा. जयशंकर ने वियतनाम के विदेश मंत्री ले होई ट्रुंग के साथ भी बैठक की। उन्होंने कहा कि इस दौरान रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय आर्थिक संबंध को और गहरा करने पर चर्चा हुई।

स्वदेशी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्षमता के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) प्लेटफ़ॉर्म के रूप में और आपात स्थिति में अस्पताल जहाज के रूप में कार्य करने में सक्षम है।

इक्षक महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाये गये आवास की सुविधा वाला पहला एसवीएल जहाज भी है जो भविष्य के लिए तैयार बेड़े के प्रति भारतीय नौसेना के समावेशी और प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है।

राम मंदिर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी देश-दुनिया के भक्तों से सोशल मीडिया के जरिये साझा की। उन्होंने बताया कि 161 फीट ऊंचे राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मंदिर का दूसरा तल पूरी तरह से बनकर तैयार है।

अब केवल फिनिशिंग का काम चल रहा है। अगले एक पखवाड़े के भीतर यह काम भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि सप्त मंडप के सात मंदिरों (महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, शबरी, ऋषि पत्नी अहिल्या) का निर्माण भी पूरा हो गया है। संत तुलसीदास का मंदिर भी पूरा हो गया है। गिद्ध राज जटायु और गिलहरी की मूर्ति भी परिसर में स्थापित हो गई है। ट्रस्ट महासचिव के अनुसार, दर्शनार्थियों की सुविधा और व्यवस्था से सीधे जुड़े सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

बताया कि, ध्वजारोहण समारोह के बाद परिसर के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं को दर्शन मिलने लगेंगे।

स्ट्रीट डॉग्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने प.बंगाल व तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया

- इन सभी राज्यों को स्ट्रीट डॉग्स पर 22 अगस्त तक अनुपालना रिपोर्ट देनी थी।

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को हलफनामा दाखिल न करने पर तलब किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही कंप्लायंस एफिडेविट फाइल किया है। अदालत ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के अलावा, बाकी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को 3 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया।(22 अगस्त को, कोर्ट ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कम्प्लायंस एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया था। आज, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने नोट किया कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही कम्प्लायंस एफिडेविट फाइल किया है।

मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि कोर्ट ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों को नोटिस जारी किया था और आदेश की बड़े पैमानें पर रिपोर्टिंग भी हुई थी। जस्टिस नाथ ने कहा, "लगातार घटनाएं हो रही हैं और देश की इमेज दूसरे देशों की नजर में खराब हो रही है। हम न्यूज रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं।"(जस्टिस नाथ ने खास तौर पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से यह भी पूछा कि दिल्ली सरकार ने एफिडेविट क्यों फाइल नहीं किया है।

जस्टिस नाथ ने कहा, " एनसीटी ने एफिडेविट फाइल क्यों नहीं किया? चीफ सेक्रेटरी को एक्सप्लेनेशन देना होगा...नहीं तो, कॉस्ट लगाई जा सकती है और सख्त कदम उठाए जाएंगे...सभी राज्यों/ यूटीएस को नोटिस जारी किए गए थे...आपके ऑफिसर अखबार या सोशल मीडिया नहीं पढ़ते? सभी ने इसकी रिपोर्ट की है...जब उन्हें पता चलेगा, तो उन्हें आगे आना चाहिए! सभी चीफ सेक्रेटरी 3 नवंबर को मौजूद रहें, नहीं तो हम कोर्ट ऑडिटोरियम में करेंगे।"

अमेरिका के विदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मॉस्को के साथ अपने संबंधों को लेकर नई दिल्ली पर दबाव बनाने में कोई संकोच नहीं किया है। रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों में शामिल होने से भारत का इनकार वाशिंगटन को लगातार परेशान कर रहा है। इसलिए, रुबियो की यह नरम पहल यह स्वीकारोक्ति भी है कि दबाव की एक सीमा होती है, और अनुनय-विनय तब ज़्यादा कारगर होती, जब भारत को अमेरिकी रणनीतिक दायरे में बनाए रखना लक्ष्य हो।

नई दिल्ली के दृष्टिकोण से, इस बैठक ने दोहरा उद्देश्य भी पूरा किया। इसने वाशिंगटन को याद दिलाया कि भारत के साथ साझेदारी स्वतः नहीं होती, इसे भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं और रणनीतिक स्वायत्तता के सम्मान के माध्यम से अर्जित किया जाना चाहिए। जयशंकर के संयमित स्वर, जिसमें उन्होंने "पारस्परिक हितों और पारस्परिक संवेदनशीलता" पर ज़ोर दिया, ने शांत दृढ़ता का संकेत दिया। भारत, अमेरिकी जुड़ाव का स्वागत करता है, लेकिन किसी के दबाव या निर्देश में नहीं चलेगा भारत। अंततः, रुबियो की यह पहल तात्कालिक परिणामों से ज्यादा प्रतीकात्मक विश्वास बहाली की कोशिश थी, यह दिखाने के लिए कि ट्रंप की अनिश्चित नीतियों के बावजूद, अमेरिकी व्यवस्था के कुछ हिस्से अभी भी भारत को अमेरिका के दीर्घकालिक हितों के केन्द्र में देखते हैं। यह संदेश भारतीय जनता का भरोसा दोबारा जीत पाएगा या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस कूटनीति ने दोनों देशों के रिश्तों में कुछ राहत और शायद थोड़ी और उम्मीद पैदा की है।

पुणे में पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी

पुणे, 27 अक्टूबर। महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने सोमवार को पुणे में कई जगहों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में एटीएस ने 28 वर्षीय जुबेर हंगरगीकर को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई कोंढ वा इलाके में की गई। यह कार्रवाई आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने के संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ की गई है। हंगरगीकर को 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। एटीएस ने 9 अक्टूबर को पुणे में आतंकवाद से जुड़े एक मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी।

इस तलाशी अभियान में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज़ और साहित्य ज़ब्त किए गए थे। जांच के दौरान सामने आई आपत्तिजनक सामग्री के आधार पर, 2008 में

- तलाशी के दौरान एटीएस को आपत्तिजनक साहित्य, इलैक्ट्रोनिक उपकरण एवं दस्तावेज मिले।

संशोधित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद, एटीएस ने जुबेर हंगरगीकर को गिरफ्तार कर लिया। मामले की आगे की जाँच महाराष्ट्र एटीएस द्वारा की जा रही है।

इससे पहले, पुलिस ने दिल्ली में आईएसआईएस से प्रेरित एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी के दौरान दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों में से एक दिल्ली का रहने वाला है, जबकि दूसरा मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, दोनों आतंकवादी आईईडी विस्फोट की योजना बना रहे थे और अपनी योजना के अंतिम चरण में थे। जाँच में यह भी पता चला है कि ये आतंकवादी आत्मघाती हमलों का प्रशिक्षण ले रहे थे। गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्ध आईएसआईएस मॉड्यूल का हिस्सा हैं और विस्फोट के लिए पूरी तरह तैयार थे।

सीजेआई गवई पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि सीजेआई ने उदारता दिखाते हुए राकेश किशोर को माफ कर दिया है, इसलिए इस मामले को समाप्त माना जाएगा। हालांकि, अदालत ने ऐसे कृत्यों के महिमामंडन और भविष्य में रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार जारी रखने का संकेत दिया।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना और सोशल मीडिया पर महिमामंडन रोकने के लिए आदेश की मांग की गथी। एससीबीए के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि शुरुआत में मामला समाप्त हो गया था, जब सीजेआई ने किशोर को माफ कर दिया था, लेकिन राकेश किशोर ने मीडिया से कहा कि भगवान ने मुझसे ऐसा करवाया और इस पर सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं, जिससे न्यायपालिका का मजाक बन रहा है।

विकास सिंह ने बताया कि राकेश किशोर ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए अपने कृत्य को दोहराने की कसम भी खाई। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने स्वीकार किया कि राकेश किशोर का व्यवहार गंभीर आपराधिक अवमानना जैसा है, लेकिन जब सीजेआई ने माफ कर दिया, तो यह मामला आगे नहीं बढ़ सकता। जस्टिस बागची ने स्पष्ट किया कि न्यायालय की अवमानना के मामलों में अवमानना कार्रवाई का निर्णय संबंधित जज पर निर्भर होता है।

आखिर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तक कि जेडीयू नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कथित तौर पर बीमार हैं, भी दर्जनों सभाओं को संबोधित कर चुके हैं, जैसे कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया है। जेएसपी नेता प्रशांत किशोर भी लगातार प्रचार दौरे पर हैं। इस बीच, राहुल गांधी को पुरानी दिल्ली की गलियों में 'इनमार्टिस (हस्तशिल्प) तैयार करते हुए देखा गया है।

कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनावों में बिहार की तीन सीटों पर जीत हासिल की थी, जिनमें से दो सीटें सीमांचल क्षेत्र में है, जो पश्चिम बंगाल सीमा के पास स्थित हैं, और जहां मतदान दूसरे चरण में 11 नवम्बर को होना है। 2020 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था तथा 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अगर कांग्रेस इन आंकड़ों में सुधार करना चाहती है, तो चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। समय की कमी को देखते हुए, यह देखना होगा कि राहुल गांधी वह ऊर्जा और जादू दोबारा उत्पन्न कर पाते हैं कि नहीं, जो उन्होंने वोट अधिकार यात्रा के दौरान पैदा किया था।

बांग्लादेश के प्रमुख यूनुस ने पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश का हिस्सा बताया

मोहम्मद यूनुस ने पाक जनरल को एक किताब दी है जिसमें बांग्लादेश के नक्शें में भारत का पूर्वोत्तर भाग भी है

- यूनुस ने पाक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को "आर्टऑफ ट्रायम्फ" भेंट की, जिसके कवर पर प्रदर्शित नक्शें में असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सातों राज्य बांग्लादेश के हिस्से के रुप में प्रदर्शित किए गए हैं।

ढाका, 27 अक्टूबर। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मुहम्मद यूनुस द्वारा एक पाकिस्तानी जनरल को दिए उपहार ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक विवादास्पद किताब "आर्ट ऑफ ट्रायम्फ" भेंट की, इस किताब के कवर पर छपे नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। यूनुस के इस कदम को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुद्दे पर कूटनीतिक हलचल उत्पन्न करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

बांग्लादेश यात्रा पर पहुंचे पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को आर्ट ऑफ ट्रायम्फ भेंट की थी। जिसकी कवर पर दिखाए गए नक्शे में भारत के सातों पूर्वोत्तर राज्य असम से लेकर अरुणाचल तक को बांग्लादेश का हिस्सा दर्शाया गया है। बांग्लादेश सरकार के अंतरिम प्रमुख की इस हरकत की जमकर आलोचना भी की जा रही है।

इस पूरे मामले पर भारत सरकार की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ जुलाई-अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान दीवारों पर बनाई गई ग्रैफिटी और अन्य चित्रों से भरी है।

जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इस सप्ताहांत बांग्लादेश का दौरा ऐसे समय पर किया, जब दोनों देशों के बीच रिश्तों में करीबी बढ़ रही है। शमशाद मिर्जा पाकिस्तानी सेना में नंबर दो की हैसियत रखते हैं। जानकारी के मुताबिक, यूनुस पहले भी इस किताब को कुछ अन्य विदेशी हस्तियों को भेंट कर चुके हैं।

यह पहली बार नहीं है, जब यूनुस की ओर से इस तरह की हरकत की गई है। पिछले कुछ महीनों में वह विदेशों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों का कई बार जिक्र कर चुके हैं। अप्रैल में अपनी पहली चीन यात्रा के दौरान यूनुस ने यह दावा करके नई दिल्ली को नाराज कर दिया था कि बांग्लादेश इस क्षेत्र के लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षक है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत भूमि से घिरा है। इसके जरिये उन्होंने चीन को इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ ाने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया।

भारत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कई अन्य मुद्दों पर भी मतभेद बने रहे।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के सकारात्मक घटनाक्रमों की जानकारी मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कलकत्ता में भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स ने आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि सभी अड़चनें दूर हो गई हैं लेकिन समझौते में रुकावट डालने वाले कुछ नए मुद्दे भी हैं।

इस बीच, अमेरिका और चीन ने भी कथित रूप से अपने व्यापार विवादों को सुलझा लिया है और वे परस्पर व्यापार के लिए एक रूपरेखा समझौते पर पहुँचने के करीब हैं।

ट्रंप ने चीनी निर्यात पर भी शुल्क लगाए थे, लेकिन वे इन्हें लागू करने में बार-बार पीछे हटते रहे और कभी नरम तो कभी सख्त रुख अपनाते रहे। दरअसल वे चीन की संभावित जवाबी कार्रवाई से डर रहे थे।

चीन के पास अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा हथियार था, "दुर्लभ खनिज" का वैश्विक बाज़ार, जिस पर उसका नियंत्रण है। ये खनिज रक्षा वस्तुओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामानों तक, हर क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक हैं। चीन ने अमेरिका को इन खनिजों की सभी शिपमेंट रोकने की धमकी दी थी, जिसके बाद अमेरिका को पीछे हटना पड़ा।

'एसआईआर लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए'

श्रीनगर, 27 अक्टूबर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।।

अब्दुल्ला ने विधानसभा सत्र के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में एसआईआर के कार्यान्वयन को लेकर पहले ही कुछ शिकायतें आ चुकी हैं। उन्होंने कहा, "हमें यह भी नहीं पता कि एसआईआर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा या नहीं जिन्हें यह मिलेगा। पहले बिहार में चुनाव पूरे हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे कि एसआईआर वाकई फायदेमंद है या नहीं।"मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह इस प्रणाली को कहीं और लागू करने से पहले नतीजों का इंतज़ार करे। उन्होंने कहा, "बिहार के नतीजे अभी नहीं आए हैं। चुनाव आयोग को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि तब ऐसा लगेगा कि आयोग अपनी स्वतंत्रता खो रहा है और किसी राजनीतिक दल के दबाव में काम कर रहा है।"

- जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि बिहार के नतीजे आने के बाद ही एसआईआर का दूसरा चरण शुरु होना चाहिए।

अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का हवाला देते हुए आरोप लगाया, "हमने पहले भी देखा है कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन यहाँ के लोगों के लाभ के लिए नहीं किया गया था। यह एक खास राजनीतिक दल को लाभ पहुँचाने के लिए किया गया था।" उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीटों का बंटवारा